माननीय न्यायमूर्ति सुरिंदर सिंह के समक्ष

इंद्रावती-वादी-याचिकाएं,

बनाम

जगमाल और एक अन्य- *प्रतिवादी-उत्तरदाता।*

1978 का सिविल संशोधन संख्या 475

13 अक्टूबर, 1978।

*हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम (*1956 *का 32*) - धारा *16* और *30* - अधिनियम के पारित होने से पहले किया गया दत्तक ग्रहण - इसके संबंध में प्रमाण का बोझ - क्या यह उस व्यक्ति पर है जो गोद लेने के आधार पर दावा करता है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम 1956 की धारा 30 में विशेष रूप से यह प्रावधान है कि इसमें निहित कुछ भी अधिनियम के प्रारंभ से पहले किए गए किसी भी दत्तक ग्रहण को प्रभावित नहीं करेगा और इसलिए इस तरह के किसी भी दत्तक ग्रहण की वैधता और प्रभाव को इस तरह निर्धारित किया जाना चाहिए जैसे कि अधिनियम पारित नहीं किया गया था। इसलिए, गोद लेने के प्रश्न पर बोझ डालने के संबंध में सामान्य कानून पर वापस लौटना होगा; यदि अधिनियम लागू होने से पहले ऐसा हुआ होता। सामान्य कानून यह है कि गोद लेने के समर्थन में सबूत उस गंभीर और गंभीर जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए जो किसी भी व्यक्ति पर निर्भर करता है जो गोद लेने का आरोप लगाकर प्राकृतिक उत्तराधिकार को विस्थापित करना चाहता है । इस प्रकार, इस तरह के गोद लेने को साबित करने का बोझ उस व्यक्ति पर है जो गोद लेने के आधार पर दावा करता है।

(पैरा 2)

सी.पी.सी. की धारा 115 *के तहत श्री एस. डी. अरोड़ा, उप न्यायाधीश* प्रथम *श्रेणी, चरखी दादरी के दिनांक* 16 फरवरी, 1978 *के आदेश में संशोधन के लिए याचिका दायर की गई है।*

याचिकाकर्ता की ओर *से अधिवक्ता एनसी जैन।*

आर. एस. मित्तल, वकील, *उत्तरदाताओं के लिए।*

इंद्रावती *बनाम* जगमाल और एक अन्य (सुरिंदर सिंह, जे।

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति सुरिंदर सिंह (मौखिक)

1) प्रतिवादियों के खिलाफ इंद्रावती याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक घोषणात्मक मुकदमे में, एक आरोप लगाया गया था कि जगमाल, प्रतिवादी, जिसने श्रीमती करियन के वैध रूप से दत्तक पुत्र होने का दावा किया था, प्रतिवादी वास्तव में ऐसा नहीं था। निचली अदालत ने पक्षकारों की दलीलों के परिणामस्वरूप जगमाल को श्रीमती करियान के पुत्र के रूप में कथित रूप से गोद लेने के संबंध में एक मुद्दा तैयार किया और ऐसा करते समय इस तथ्य को साबित करने की जिम्मेदारी वादी पर डाल दी कि जगमाल श्रीमती करियन का वैध रूप से दत्तक पुत्र नहीं था। याचिकाकर्ता ने तब ट्रायल कोर्ट से प्रार्थना करते हुए एक आवेदन दायर किया कि जिम्मेदारी गलत तरीके से उस पर रखी गई थी और वास्तव में, यह साबित करने की जिम्मेदारी कि जगमाल श्रीमती करियन का वैध रूप से दत्तक पुत्र था, उस पर रखा जाना चाहिए था, क्योंकि गोद लेना, इसकी प्रकृति से, उत्तराधिकार की प्राकृतिक प्रक्रिया के खिलाफ है। आवेदन पर ट्रायल द्वारा विचार किया गया

था। अदालत और 16 फरवरी, 1978 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।

2) मैंने उपर्युक्त मुद्दे पर पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुना है, जो वास्तव में इस पुनरीक्षण याचिका में उठाया गया एकमात्र मुद्दा है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने मेरा ध्यान हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम, 1956 की धारा 16 और 30 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया है, (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित)। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि वर्तमान मामले में कथित दत्तक ग्रहण एक पंजीकृत दस्तावेज के माध्यम से है जिसे वर्ष 1962 में निष्पादित किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि वास्तविक दत्तक ग्रहण वर्ष 1952 में हुआ था, यानी अधिनियम के लागू होने से पहले। अधिनियम की धारा 16 के तहत, जब भी किसी कानून के तहत पंजीकृत कोई दस्तावेज किसी भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जो गोद लेने को रिकॉर्ड करने का दावा करता है, तो अदालत को यह मानना होगा कि गोद लेने का काम इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया है जब तक कि इसे अस्वीकार नहीं किया जाता है। तथापि, अधिनियम की धारा 30 के अधीन यह विशेष उपबंध किया गया है कि इस अधिनियम में निहित कोई भी बात इस अधिनियम के लागू होने से पहले किए गए किसी दत्तक ग्रहण को प्रभावित नहीं करेगी और ऐसे किसी दत्तक ग्रहण की वैधता और प्रभाव का निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा जैसे कि यह अधिनियम पारित नहीं किया गया था। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, कहा जाता है कि वास्तविक दत्तक ग्रहण वर्ष 1952 में हुआ था, अर्थात अधिनियम के लागू होने से पहले। अधिनियम की धारा 30 के आधार पर, हम वादी-याचिकाकर्ता पर गोद लेने को साबित करने का बोझ डालने के उद्देश्य से धारा 16 की सहायता नहीं मांग सकते हैं। यदि उक्त अधिनियम के उपबंधों की अनदेखी की जाती है, तो हमें दत्तक ग्रहण के प्रश्न पर भार डालने के संबंध में सामान्य कानून की ओर लौटना होगा। इस संबंध में, मुल्ला के हिंदू कानून (तेरहवें संस्करण) के पैरा 512 का संदर्भ दिया गया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि गोद लेने के समर्थन में साक्ष्य उस बहुत गंभीर और गंभीर जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए जो किसी भी व्यक्ति पर निर्भर करता है जो गोद लेने का आरोप लगाकर प्राकृतिक उत्तराधिकार को विस्थापित करना चाहता है। रणजीत साहू बनाम नीलांबर साहू और एक अन्य, (1) में पूर्वोक्त के अनुसार कानून के शासन को दोहराया गया है। उक्त मामला, निश्चित रूप से, अधिनियम के तहत गोद लेने के सवाल से संबंधित था, लेकिन चर्चा के दौरान, विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि अधिनियम के अलावा, गोद लेने के आधार पर दावा करने वाले व्यक्ति पर भारी बोझ पड़ता है। कानून की इस स्थिति में, ट्रायल कोर्ट का आदेश जो दत्तक ग्रहण को साबित करने का भार याचिकाकर्ता पर डालता है, स्पष्ट रूप से अवैध है और इसे उलटने की आवश्यकता है।

3) इस पुनरीक्षण याचिका में किसी अन्य बिंदु पर तर्क नहीं दिया गया है। ट्रायल कोर्ट के आक्षेपित आदेश को इस हद तक उलट दिया जाता है कि मुद्दा नंबर 1 साबित करने का बोझ याचिकाकर्ता के बजाय उत्तरदाताओं पर रखा जाएगा। कानून के अनुसार आगे की कार्यवाही के लिए मामला ट्रायल कोर्ट में वापस जाएगा।

पक्षकारों को उनके वकील के माध्यम से 2 नवंबर, 1978 को ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

हिमांशु जांगड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी